अमृत मिशन का द्वितीय चरण

प्रिलिम्स के लिये:

अमृत मिशन

मेन्स के लिये:

अमृत मिशन का महत्त्व और संबंधित मुद्दे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने **कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (AMRUT 2.0)** के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।

- आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय (MoHUA) योजना के लिये नोडल मंत्रालय है।

प्रमुख बिंदु

- **अमृत मिशन के बारे में:**
  - **अमृत मिशन** को हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ सभी की नल तक पहुँच को सुनिश्चित करने के लिये जून 2015 में शुरू किया गया था।
  - अमृत 2.0 का लक्ष्य लगभग 4,700 ULB (शहरी स्थानीय निकाय) में सभी घरों में पानी की आपूर्ति के मामले में 100% कवरेज प्रदान करना है।
  - इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स **(पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप)** को प्रोत्साहित करके **आत्मनिर्भर भारत** पहल को बढ़ावा देना है।
- **उद्देश्य:**
  - यह पानी की ज़रूरत को पूरा करने, जल निकायों को फिर से जीवंत करने, जलभृतों का बेहतर प्रबंधन, उपचारित अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग करने के लिये अमृत मिशन की प्रगति सुनिश्चित करेगा, जिससे पानी की एक **चक्रीय अर्थव्यवस्था** को बढ़ावा मिलेगा।
  - यह 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज का 100% कवरेज प्रदान करेगा।
  - उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग से शहरों की कुल पानी की ज़रूरत का 20% तथा औद्योगिक मांग का 40% पूरा होने की उम्मीद है। मिशन के तहत प्राकृतिक संसाधनों का टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करने के लिये स्वच्छ जल निकायों को प्रदूषित होने से बचाया जाएगा।
  - जल के समान वितरण, अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग और जल निकायों के मानचित्रण का पता लगाने के लिये शहरों में पेयजल सर्वेक्षण किया जाएगा।
- **अमृत मिशन के पहले चरण का प्रदर्शन:**
  - अमृत मिशन के तहत शहरों में 1.14 करोड़ नल कनेक्शन के साथ कुल 4.14 करोड़ कनेक्शन किये गए हैं।
  - 470 शहरों में क्रेडिट रेटिंग का काम पूरा हो चुका है। इनमें से 164 शहरों को **निवेश योग्य ग्रेड रेटिंग (IGR)** प्राप्त हुई है, जिसमें 36 शहर **A-** या उससे ऊपर की रेटिंग वाले हैं।
  - 10 ULB ने **म्युनिसिपल बॉण्ड** के ज़रिये 3,840 करोड़ रुपए जुटाए हैं। ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली को 455 अमृत शहरों सहित 2,471 शहरों में लागू किया गया है।
  - इस सुधार से वर्ष 2018 की विश्व बैंक की **डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट** (डीबीआर) की भारतीय रैंकिंग 181 रैंक से वर्ष 2020 में 27 हो गई।
  - 89 लाख पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा कुशल एलईडी लाइटों से बदल दिया गया है, जिससे प्रतिवर्ष 195 करोड़ यूनिट की अनुमानित ऊर्जा बचत और CO_2 उत्सर्जन में प्रतिवर्ष 15.6 लाख टन की कमी आई है।

स्रोत: पीआईबी

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/2th-phase-amrut-mission